की जाती है, तो उसका निर्णय अन्तिम नहीं होता है। सरकार जो निर्णय लेती है, जब इस सदन के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है, तो वह इस देश के लिए अन्तिम निर्णय होता है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है।

श्री शिव नारायण ने कहा है कि इनटेरिम रिलीफ की घोषणा 2 अक्तूबर से पहले की जानी चाहिये, मैं तो कहता हूं कि वह घोषणा 2 अक्तूबर से पहले हो जावे लेकिन अगर 2 अक्तूबर से पहले नहीं होती है, तो मुझे खुशी होगी। अगर वह 2 अक्तूबर तक कर दी जाये। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बात पे कमीशन को सोचनी चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि सरकार ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाती है कि जिस तरह से कीमतों में वृद्धि होती है, उसी तरह से कर्मचारीगण के वेतन में भी वृद्धि कर दी जाये। इस तरह का फार्मूला बना हुआ है, जिसे हम गजेन्द्रगड़कर फार्मूला कहते हैं और जो हमारे आलइंडिया वर्किंग क्लास कनज्यूमर प्राइस इन्डेक्स से संबंधित हैं। यह निर्णय और समझौता हो चुका है कि ट्वेल्व मंथली ऐवरेज, बारह महीनों का औसत, 10 पाइंट बढ़ जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों का डीयरनेस एलाउन्स उसी हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। 1968 में इसी फार्मूले के अनुसार डीयरनेस एलाउन्स का रिविजन किया गया। यदि ट्वेल्व-मन्थली ऐवरेज फिर 10 पाइंट बढ़ जायेगा, तो डीयरनेस एलाउन्स भी फिर बढ़ा दिया जायेगा। यह फार्मूला बना हुआ है और समय समय पर उसके अनुसार कार्यवाही होती रहती है।

माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द वर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकारी कर्मचारियों के साथ है और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके मन में बड़ी भारी सद्भावना है। मैं इस बात को मानता हूं। श्री वर्मा जितने जोरों से सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जितनी चिन्ता विरोधी दलों के सदस्यों को है, उतनी चिन्ता श्री वर्मा और उनके दल वालों को भी है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

17.48 hrs.

## STATEMENT RE: CLOSURE OF SHAHDARA-SAHARANPUR LIGHT RAILWAY

**सभापति महोदय :** अब माननीय सदस्य, श्री गोयल, के नाम से एक हाफ-एन-आवर डिसकशन है। चूंकि श्री गोयल इस समय सदन में नहीं हैं, इसलिए नियम के मुताबिक यह डिसकशन लेप्स हो जाता है। (**व्यवधान**) मैं नियम को सस्पेंड नहीं करूंगा। यह डिसकशन लेप्स हो जाता है।

रेलवे मिनिस्टर साहब ने एस० एस० लाइट रेलवे के बारे में जो स्टेटमेंट देने का वादा किया था, वह अब वह स्टेटमेंट देंगे।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (हापुड़) : सभापति महोदय, हम लोगों ने इस विषय पर कितने ही कालिंग एटेन्शन नोटिस और शार्ट नोटिस क्वेश्चन आदि दे रखे हैं। मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद आप हमें कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दे दे।

**सभापति महोदय :** अभी तक यह परम्परा चली आई है कि स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन एलाऊ नहीं किये जाते हैं। इसलिए मैं माफी चाहता हूं।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** सभापति महोदय, फिर मेरा प्वाइंट आफ आर्डर सुन लीजिए। इसी आसन से जहां आप इस समय बैठे हैं यह व्यवस्था दी गई थी कि अगर किसी सदस्य की ओर से ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव पहले आएगा किसी विषय पर तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायगा और सर-

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कार की ओर से व्यक्तव्य देने की सूचना पहले आएगी तो सरकार का वक्तव्य पहले लिया जायगा । यह आप अपने कार्यालय से पूछ लीजिए कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले आया है या मंत्री महोदय के वक्तव्य देने की सूचना पहले आई है ? अगर हमारा प्रस्ताव पहले आया है तो हम चाहते हैं कि हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय ।

**सभापति महोदय:** यह तो हाऊस में तय हुआ था कि मंत्री महोदय स्टेटमेंट हाउस में देंगे । तो उसी विषय पर वह स्टेटमेंट दे रहे हैं ।

**श्री प्रकाश वीर शास्त्री:** इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने दिया है । आप अपने कार्यालय से पूछ लीजिए कि वह पहले आया हैं या रेल मंत्री की सूचना पहले आई है ?

**सभापति महोदय:** पहले स्टेटमेंट आप लोग मेहरबानी करके सुन लीजिए । अगर जरूरी होगा तो एक दो आदमियों को जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया था उनको मैं एलाऊ करूंगा । लेकिन सबको मैं एलाऊ नहीं करूंगा ।. . . (व्यवधान) अगर यह बात होगी तो मैं किसी को एलाऊ नहीं करूंगा ।

**श्री स० मो० बेनर्जी:** (कानपुर) आज सुबह जब अध्यक्ष महोदय यहां मौजूद थे तो मेरे मित्र प्रकाशवीर शास्त्री जी ने यह मामला उठाया तो हम लोगों ने, सभी ने उसका समर्थन किया कि कालिंग अटेंशन नोटिस लिया जाय . . .

**सभापति महोदय:** वह बात तो हो गई । अब स्टेटमेंट होने दीजिए ।

**श्री स० मो० बेनर्जी:** अगर यह एस० एस० लाइट रेलवे खत्म नहीं होगी तो हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे । लेकिन अगर खत्म होती है . . . (व्यवधान) . . .

**सभापति महोदय:** आप मेहरबानी करके बैठिए । उनको स्टेटमेंट करने दीजिए ।

SHRI NANDA: Sir, the statement runs to more than two pages.

SHRI S. KUNDU: (Balasore): Please read it. You are going to take away the bread of 1,500 people.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA): Please listen; do not accuse us. They are not employees of the Indian railways. I shall read the statement now.

From the day I came to know of the notice of closure issued by the Company on 15th July, 1970, I have personally been in close and frequent touch with the employees of the Company and their representatives. I have discussed with them at length various courses which are open for meeting the threat of unemployment to nearly 1,200 workers. These discussions were carried on today also and will continue. We have made strenuous efforts to secure from the Company a postponement of the stoppage for period of three months to enable us to work out a suitable method of dealing with the problem. These efforts have not fructified. (*Interruptions*).

I have been in touch with the Labour Ministry to ensure that the Company is made to pay the dues of the workers and discharge its obligations to them (*Interruptions*.) It seems that till the retrenchment compensation and other arrears are paid to employees, they would continue as employees of the Company although it stops operating on the line.

I may mention here that the S.S. Light Railway (Narrow Gauge; 149 kms.) is run by the S. S. Light Railway Company from Shahdara (Delhi) to Saharanpur. The Railway Company operates under an agreement originally made with the Government of Uttar Pradesh, which is now operative with the Central Government by virtue of Government of India Act, 1935. Government

of India have an option to purchase this at intervals of seven years. The last date of option to purchase was 1st April, 1969, and it was decided well before that date—Shri C.M. Poonacha was the Railway Minister then—not to purchase the line as it was not financially remunerative. In July 1970, we informed the U. P. Government that the Government of India did not propose to nationalise the light Railway and urged the State Government to run it at least for some time more, for which there was a precedent in West Bengal. Regarding the staff, I requested the Chief Minister, U.P. to absorb them in the U.P. Road Services and if there were still any surplus staff, I said they could be considered for absorption on the Northern Railway, subject to their suitability. (*Interruptions*).

We have not received any reply to the letter so far. I spoke to the Chief Minister of U.P. on the night of 29th and it has been agreed that the U.P. Government will depute Secretary of the Government to hold consultations with us regarding the best way of dealing with this problem. The Company has been making losses almost every year since 1957-58 and the total of losses is more than the paid-up capital of the Company. It is urged by them that the buses and trucks, that are being permitted to play on the road run more or less parallel to the Railway line, have cut into the revenues of the Company and it cannot now afford to keep running and incur further losses.

Shri Ram Subhag Singh made a very categorical statement in the House to-day that he and other Railway Ministers in the past have made commitment in favour of nationalisation. In the interval after the question was raised in the House to-day, I made inquiries and I find that on 26-8-69, when replying to Unstared Question No. 5028 in the Lok Sabha, Dr. Ram Subhag Singh stated that the question of purchase of S. S. Light Railway was considered by the Government recently in connection with the latest option of purchase under the Agreement which fell due in April, 1969 and that after taking into account all the relevant factors, it was decided not to purchase this Railway (*Interruptions*).

The rolling stock and other assets of the Railway are in a wornout condition, because there have been practically no replacements and renewals since 1961-62. Apart from the purchase price of Rs. 72 lakhs, Rs. 42 lakhs will be required immediately to rehabilitate the assets and even then the Railway will not be paying, because of severe road competition, both in respect of passenger and goods traffic.

**18 hrs.**

The staff have thought of forming a cooperative society and running the railway themselves by putting their Provident Fund money and other dues from the Company but I am afraid such a society will also run into losses so long as the road competition is there. I could not advise the employees to embark on this venture because thereby they would be frittering away their hard-earned savings. The best course, in my opinion, would be to form one or two cooperative societies to run the road services in the region and the State Government should be urged to issue licences in favour of these cooperative societies formed by the employees, and not to any other person. Even if the Railway has to be run on a cooperative basis by the employees themselves, it will not be a workable proposition, so long as the U.P. Government does not put a stop to any further road competition by issuing licences to buses and trucks.

**सभापति महोदय:** मुझे एक बात कहनी है, उस को पहले सुन लीजिए। इसके बारे में काल-एटेन्शन रिजेक्ट हो चुका था...

**श्री स० मो० बनर्जी:** नहीं हुआ था।

**सभापति महोदय:** हम को आफिस की तरफ से ऐसा कहा गया है। चूंकि शास्त्री जी ने यह सवाल उठाया है, इसलिये मैं शास्त्री जी को एज ए स्पेशल केस प्रश्न पूछने की परमीशन देता हूं.. (**व्यवधान**)..

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री:** अगर आपने केवल मुझे ही प्रश्न पूछने की अनुमति देनी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र श्री रघुवीर सिंह जी शास्त्री को, जिनके निर्वाचन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

क्षेत्र से यह लाइन गुजरती है, प्रश्न पूछने का अवसर दे दिया जाय ।

SHRI S. KUNDU: And those of us who are connected with the Unions.

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** (बागपत) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने डा० राम सुभग सिंह जी के उत्तर का यह उद्धरण तो दिया, परन्तु क्या यह ठीक नहीं है कि उन्होंने जानबूझ कर वह बात नहीं कही, जिस में डा० राम सुभग सिंह ने कहा था—क्योंकि यह इलाका ऐसा है, जिसमें नैरोगेज लाइन इस इलाके की आवश्यकता पूरा नहीं करती है, इस लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया का यह विचार है यहां ब्राडगेज लाइन बनाई जाय और उसके लिये सर्वे किया जाय तथा गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में सर्वे किया भी है—इस के सम्बन्ध में नन्दा जी ने कुछ नही कहा . . .

**श्री रणजीत सिंह** (खलीलाबाद) : शर्म आनी चाहिये . . .

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्राड गेज लाइन बनाने के लिये जो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का कमिटमेंट है, जिसका सर्वे हो चुका है, वह कब तक करेंगे तथा उसके सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

दूसरी बात—मैं समझता हूं कि वह सारी बातों को बचाने के लिये एक भूमिका बना रहे हैं—उन्होंने कहा कि रोड के साथ बड़ा कम्पीटीशन है, मुझे बता दीजिये कि इस समय कौन सी ऐसी रेलवे है, जिसके साथ रोड का कम्पीटीशन नहीं है, सब जगह सड़कें हैं, फिर भी सरकार की रेलवे लाइन्स फायदे में चलती हैं, बड़ी लचर दलील आपने दी है ।

तीसरी बात—क्या आपने कम्पनी के एकाउन्ट्स और बैलेन्सशीट, जिसके बारे में हमारा हमेशा चेलेन्ज रहा है कि वे फिक्टीशस, मनगढ़न्त और झूठी बनाते हैं, को एक्जामिन कराया है, जो घाटा वे दिखाते हैं, यह ठीक है या गलत है ?

चौथी बात—कर्मचारियों के संबंध में आपने बिलकुल गोलमाल बात की है, कभी कहते हैं कि यह करेंगे, कभी कहते हैं कि वह करेंगे, कभी कहते हैं कि यू० पी० गवर्नमेंट को लिखा है । यू० पी० गवर्नमेंट से इसका क्या ताल्लुक है, क्या यू० पी० गवर्नमेंट रेलवे चलाती है, रेलवे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी को आप यू० पी० गवर्नमेंट के मत्थे थोपना चाहते हैं । कर्मचारियों को खपाने की जिम्मेदारी नैतिक तौर पर आपकी है, आपको उन्हें नार्दर्न रेलवे में खपाना चाहिये—इस के बारे में आपको स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये । उस कम्पनी को जो इसे बन्द कर रही है, आपकी तरफ से कहा जाना चाहिये कि उनका जितना कम्पेन्सेशन होता है, जितने उनके ड्यूज हैं, वे उनको जल्द से जल्द सैटिल करे ।

आप यह आश्वासन भी दें कि उनको उनके मकानों से तब तक नहीं निकाला जायगा, तब तक उनको बिजली मिलती रहेगी, तब तक उनको पानी मिलता रहेगा, जब तक कि वे दूसरी जगह खपाये नहीं जाते । सभापति महोदय, मैं कल सहारनपुर से आया हूं, मुझे सूचना मिली है कि इस रेलवे के अधिकारियों ने कर्मचारियों को कह दिया है कि तुम हमारे मकान से निकलो, उनकी बिजली काटी जा रही है, उनका पानी काटा जा रहा है—मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये आप क्या इलाज कर रहे हैं ?

**श्री स० मो० बनर्जी :** हम लोग भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यह नहीं हो सकता कि हमको प्रश्न पूछने का मौका न मिले ।

**श्री गुलजारी लाल नन्दा :** पहली बात तो यह कही गई है कि ब्राड-गेज बनाने के

लिये कहा गया था--उस का सर्वे हो रहा है, तकरीबन पूरा होने वाला है। इसमें शर्म की क्या बात है...हमने कहा है तो क्या शर्म है...

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : मैंने शर्म नहीं कहा है।

**श्री गुलजारी लाल नन्दा** : आपने नहीं कहा है, औरों ने कहा है।

**श्री रणजीत सिंह** : मैंने कहा है... (व्यवधान)...

**श्री गुलजारी लाल नन्दा** : ब्राड-गेज का सवाल इसमें कहां था ? सवाल यह था कि क्या इसके नेशनलाइज करने का कोई कमिटमेंट हुआ था ?

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : यह कमिटमेंट था कि ब्राडगेज बनेगा।

**श्री गुलजारी लाल नन्दा** : यह दूसरी बात है।

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : आप इसे छुपा रहे हैं।

**श्री गुलजारी लाल नन्दा** : इस तरह से तो सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा, मैं तो सीधा जवाब दूंगा...(व्यवधान)... जो कुछ सही बात है, मैं तो वही कहूंगा। पहले सवाल का मैंने जवाब दिया है-- नेशनलाइजेशन का कोई कमिटमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया है। मैंने दोपहर बाद जा कर सारा रिकार्ड देखा, मुझे कहीं भी ऐसा कमिटमेंट नहीं मिला। अब आपने दूसरी बात कही है, वह नेशनलाइज करने की बात नहीं है, ब्राड-गेज के बारे में सर्वे हो रहा है...जब कम्पलीट हो जायगा, उसके बाद उसके नतीजे के बारे में फैसला होगा।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि सब जगह सड़कें हैं--मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जहां सड़कें हैं और प्राफिटेबिल्टी कम है, वहां आज भी बहुत सी लाइन्ज अनइकानामिक रूप से चल रही हैं, कितनी अनइकानामिक लाइन्ज को यह रेलवे ढोएगी। इसलिये कोआर्डिनेशन-आफ-रोड-एण्ड-रेल्वे-ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। आप अगर यह कहते चले जांय कि कोई परवाह नहीं है, दूसरी तरफ ट्रक्स बढ़ते चले जांय, बसेज बढ़ती जांय, हम यहां 50-100 लाख रुपया खर्च करते चले जांय, ट्रेफिक उससे बढ़े नहीं, तो वह चल नहीं सकता है।

SHRI S. KUNDU: Why are you investing money on this broad gauge survey? What is the principle? If you think it is so much uneconomic that you want to wind it up, why do you invest money on it?

**श्री गुलजारी लाल नन्दा** : यह बात ठीक है ब्राड-गेज ज्यादा रिम्युनरेटिव हो सकता है नैरो-गेज के मुकाबले

Broad gauge can be more remunerative than the narrow gauge इसलिये ब्राड-गेज यहां होगा या नहीं--I am not able to assure that. . . . (व्यवधान). . .

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : हम धमकाने से दबने वाले नहीं हैं। ये क्यों धमकाते हैं....

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि नन्दा जी धर्मात्मा आदमी हैं, इन्हें जो शर्म शब्द कहा गया है, उससे शायद इनका बैलेंस बिगड़ गया है। आप कृपा कर इतना कह दीजिये कि सर्वे हो रहा है, ब्राड-गेज बनेगी, यह बात कहने में क्या दिक्कत है ?

**श्री गुलजारी लाल नन्दा** : ब्राड-गेज बनेगी, इसका भी कमिटमेंट नहीं करता हूं। जब तक ब्राड-गेज के सर्वे का रिजल्ट नहीं आयेगा, सीधी सी बात है, मैं क्या कह सकता हूं ऐसे सर्वे हो रहे हैं, हर एक सर्वे के ऊपर बनाने का वायदा कैसे कर सकता हूं।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** हमारा निवेदन नम्रता से यह है कि यह 140 किलोमीटर की लाइन है और सारी आमदनी की लाइन है । आप इतना कह दीजिये कि सर्वे के बाद अगर यह रिपोर्ट आती है कि रेलवे लाइन घाटे की नहीं रहेगी तो हम ब्राड-गेज बनायेंगे –इतना कह दीजिये ।

**श्री गुलजारी लाल नन्दा :** अगर वह ठीक होगी तो बनाने का इरादा है ।

जहां तक वहां के कर्मचारियों का संबंध है, उनको क्या क्या तकलीफें है, उनको किस तरह से मदद दे सकते हैं–जैसा मैंने कहा है मैं भी उन लोगों के साथ रोज ही मिलता हूं, जो कुछ मुझ से बनेगा करूंगा । उस कंपनी को कितनी चीजों में मैं मजबूर कर सकता हूं, जो कुछ मेरे से बन सकेगा उनकी सहूलियत के लिए और उनकी मदद करने के लिए करूंगा ।

---

**18.11 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, September* 1, 1970/ *Bhadra* 10, 1892 (*Saka*).